जा रहा है। राज्य के भीतर उनके विभिन्न भागों में डीजल का वास्तविक वितरण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले डीजल के लिए राज्य सरकार डीजल की मात्रा निर्धारित करती है और ऐसा करते समय ऐसे राज्यों की स्थानीय स्थितियों के आधार पर किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता है। तेल कम्पनियां राज्यों द्वारा किये गये आबंटन का अनुसरण करती है और फुटकर बिक्री केन्द्रों को डीजल की सप्लाई करने की व्यवस्था करती हैं। तथापि राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र में डीजल सप्लाई करने के मामले में उच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ग) मिट्टी के तेल का फुटकर वितरण राज्य सरकारों का दायित्व है जिन्हें इस उत्पाद के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में कुल उपलब्धता में से उचित एवं न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता

24. श्री राम विलास पासवान :
श्री एफ० एच० मोहसिन :
श्री के० लकप्पा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा क्या है ;

(ख) क्या वे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) चालू वित्तीय वर्ष (1979-80) के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग 30 मिलियन मी० टन के लगभग होने का अनुमान लगाया गया है। देश में चालू वर्ष के दौरान शोधनशालाओं से उत्पादन की कुल पूर्वानुमानित उपलब्धता लगभग 26 मीलियन मी० टन होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1979-80 के दौरान कमी को पूरा करने के लिए लगभग 5 मिलियन मी0 टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए योजना तैयार की गई है।

Abolition of Public Schools

25. SHRI R. P. YADAV:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) keeping in view the uniformity of education in the country, whether Government are thinking of abolishing the public schools;

(b) if so, by when; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF EDUCATION, HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No proposal to abolish public schools in the country is under consideration of Government.

(b) Does not arise.

(c) The question of abolition of public schools was examined sometime back and the legal opinion tendered to the Government was to the effect that any action to abolish public schools will be violative of Article 30 of the Constitution in so far as public schools managed by minorities are concerned, and would be violative of Article 19(g) of the Constitution in so far as non-minority public schools are concerned.

Applicability of Allotment of Government Accommodation Rules uniformly

26. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government issued orders in 1975 directing Government servants who own houses in Delhi to vacate Government accommodation allotted to them;

(b) whether it is also a fact that in 1977, the Government modified the said orders allowing the house owners to retain Government accommodation on normal fees;

(c) whether it is also a fact that the priority date for allotment purposes of those Government servants who vacated the Government accommodation